यूपी ने खुद को बनाया आत्मनिर्भर

राज्य सरकार की मेहनत का असर, कमाई में केंद्र पर निर्भरता हुई कम

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। यूपी ने पिछले पांच साल में सबसे ज्यादा मेहनत आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए की है। प्रदेश ने स्वयं के करों को बढ़ाने पर जमकर मेहनत की। इसका नतीजा ये रहा कि टैक्स में अच्छा खासा राजस्व मिला।

परिवार हो या प्रदेश...बजट का फॉर्मूला एक है। उधार कम हो। उधार लें तो बेहतर निवेश के लिए लें जहां से भविष्य में अच्छा रिटर्न मिल सके। आय बढ़ाएं और खर्च घटाएं। राज्य सरकार ने इसी आधारभूत फॉर्मूले को अपनाया, जिसका नतीजा ये निकला कि वित्तीय सेहत खासी सुधर गई। वर्ष 22-23 में जहां स्वयं द्वारा जुटाया गया राजस्व करीब 1.85 लाख करोड़ रुपये था, जो 23-24 में अनुमानित 2.62 लाख करोड़ रुपये होगा। ये 50 फीसदी से ज्यादा वृद्धि है। पिछले वित्त वर्ष से तुलना करें तब भी 77 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की तेजी आई है। वहीं, पांच साल पहले यूपी की निर्भरता केंद्र पर ज्यादा थी। प्रदेश से जितना टैक्स आता था, लगभग उतना ही टैक्स केंद्रीय करों से हिस्से के रूप में मिलता था। दोनों के बीच का अंतर धीरे-धीरे बढ़ा, लेकिन पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले इस वर्ष इसमें आश्चर्यजनक तेजी आई है।

पांच वर्ष में ऐसे बढ़ा राजस्व

राजस्व वर्ष	22-23	23-24
प्रदेश का स्वयं का टैक्स	1.85 लाख	2.62 लाख
केंद्रीय करों से हिस्सा	1.69 लाख	1.83 लाख
केंद्र सरकार से सहायता अनुदान	1.11 लाख	1.01 लाख

(राशि करोड़ रुपये में)

जीएसटी, स्टांप और शराब ने किया मालामाल

राज्य सरकार के खजाने को भरने में जीएसटी नंबर एक, शराब नंबर दो और स्टांप तीसरे नंबर पर रहा। अकेले ये तीन विभाग इस वर्ष लगभग 2.43 लाख करोड़ रुपये सरकारी खजाने को देंगे। गाड़ियों की बिक्री बढ़ने का असर ये है कि करीब 13 हजार करोड़ रुपये वाहन, माल व यात्री कर के मद में सरकारी खाते में आएंगे। विद्युत कर का योगदान भी 6500 करोड़ रुपये है।

इन विभागों की कमाई में इतनी हिस्सेदारी

विभाग	22-23	23-24
जीएसटी	76709	108212
वैट	31541	41788
स्टांप	24266	34560
राज्य उत्पाद शुल्क	41349	58000
वाहन-माल व यात्री कर	8770	12672
भू राजस्व	243	962
विद्युत कर	2357	6440

(राशि करोड़ रुपये में)